

तय समय पर वितरित करें छात्रवृत्ति

समीक्षा बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश



प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 8 जून. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उद्यम व स्वरोजगार योजना में दी जाने वाली सक्मिडी व ऋण सहायता सुलभ व समय में देकर उसके उपयोग की मॉनीटरिंग भी की जाये. विभाग अपनी विभागीय प्रक्रिया को पूर्ण कराने के अलावा संबंधित हितग्राही को बैंक से समुचित सक्मिडी/ऋण दिलाने में भी हितग्राही का सहयोग करें.

उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियां उसी वर्ष तय तारीख

तक आवश्यक रूप से वितरित कर दी जाये, जिस वर्ष में वह छात्रवृत्ति देय है. विभागीय अधिकारी इसके लिए स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय करके काम करें.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि

हर गरीब का अधिकार सीधे उसके हाथों तक पहुंचाया

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय से राश्ट्रिय की भावना के साथ विगत 12 वर्ष में गरीब कल्याण के लिए टोस कार्य किया है. उनके निर्देशन में प्रत्येक मंत्रालय जनहित में सक्रिय है. हर गरीब का अधिकार सीधे उसके हाथों तक पहुंचाया गया है. इसी का परिणाम है कि देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि ऐसी अनेक योजनाएँ हैं जिनसे नागरिकों का जीवन सार्थक बना है. इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सभी पात्र राशन कार्ड धारकों नि.शुल्क खाद्यान्न, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल है.

किसी भी प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को सहज, सुलभ व समय पर लाभ देना होना चाहिए. उद्देश्य पूर्ण के लिये किसी भी तकनीकी समस्या या अन्य प्रक्रियात्मक चुटियों का तत्काल समाधान किया जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की

सभी प्रकार की वक्फ संपत्तियों की प्रविष्टियां केंद्र सरकार द्वारा संचालित उम्मीद पोर्टल पर आवश्यक रूप से की जाए तथा वक्फ संपत्तियों से संबंधित भूमि विवादों के निराकरण के लिए लगातार मॉनीटरिंग कर निराकरण सुनिश्चित किया जाए.

लगातार 100 दिन किया बिजली उत्पादन

भोपाल. प्रदेश को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन बिरसिंगपुर ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. स्टेशन की यूनिट नंबर 3 ने बीते 27 फरवरी से बिना रुके लगातार 100 दिनों तक बिजली पैदा करने का स्वर्णिम आंकड़ा छू लिया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भी कंपनी की कुल 13 उत्पादन इकाइयों ने 100 से अधिक दिनों तक लगातार निर्बाध बिजली उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया था. इस शानदार ट्रैक रिकॉर्ड में अकेले संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर का दबदबा रहा, जहां इसी यूनिट-3 ने पहले भी एक बार यह मुकाम हासिल किया था, वहीं स्टेशन की यूनिट-4 दो बार और यूनिट-5 ने एक बार इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने नाम दर्ज कराया था. मप्र पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने इस उपलब्धि पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की.

पात्र वंचित न रहे और अपात्र मतदान नहीं कर सके

समीक्षा के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने दिए निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 8 जून. मतदान सबसे पवित्र अधिकार है, उससे कोई भी पात्र मतदाता वंचित नहीं रहे. साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं कर सके.

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने यह निर्देश नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान दिये. समीक्षा राज्य निर्वाचन आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी. श्रीवास्तव ने कहा कि नाम जोड़ने और हटाने का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करें. इस कार्य की सघन मॉनीटरिंग की जाये. हर जिले में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित कर जन-प्रतिनिधियों को पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें. उन्होंने कहा कि जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये. अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं



दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर नाम हटाने की कार्यवाही करें. प्राधिकृत कर्मचारियों के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिये सुपरवाइजर की नियुक्ति करें. मतदाता सूची पुनरीक्षण

प्रक्रिया की डेसबोर्ड से ऑनलाइन नियमित मॉनीटरिंग करें. दावे आपत्ति और अपील के प्रकरणों का निराकरण सहित सभी कार्यवाहियां समय-सीमा में सुनिश्चित करें.

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने कहा कि मतदाता सूची से नाम काटने के पहले पूरी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में दावे-आपत्ति 15 जून तक लिये जायेंगे. दावे-आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जायेगा और फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जुलाई को किया जायेगा.

डिप्लोमा की 1100 सीटों पर मिलेगा प्रवेश

पशुपालन और डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन

नवभारत प्रतिनिधि भोपाल, 8 जून. मप्र कर्मचारी चयन मंडल द्वारा एनिमल हब्सैंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट के लिए आधिकारिक नियम पुस्तिका जारी कर दी गई हैम बताते प्रदेश के सरकारी और निजी महाविद्यालयों में डिप्लोमा सीटों पर प्रवेश के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है.

इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न

उद्यानिकी के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए : आयुक्त

खरीफ की तैयारी को लेकर संभागीय समीक्षा बैठक हुई

भोपाल, 8 जून. कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में इंदौर के एआईसीटीएसएल सभाकक्ष में सोमवार को रबी 2025-26 की समीक्षा एवं खरीफ-2026 की तैयारी के लिये इंदौर संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक की गई.

बैठक में कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े, प्रमुख सचिव सहकारिता डी.पी. आहूजा, उद्यानिकी विभाग के सचिव जान किंग्स ली, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खांडे, इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा, उद्यानिकी संचालक अरविंद दुबे

विशेष अभियान में चोरी गई संपत्ति बरामद

3 करोड़ से अधिक मूल्य की चोरी गई एवं ठगी गई संपत्ति बरामद

विशेष संवाददाता भोपाल, 08 जून. मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेशभर में चलाए गए चार दिवसीय विशेष अभियान के दौरान चोरी, नकबजनी और ठगी के मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चोरी गई एवं ठगी गई संपत्ति बरामद की है.

तकनीकी विश्लेषण, साइबर इनपुट और सघन विवेचना के आधार पर विभिन्न जिलों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. ग्वालियर के कोतवाली

समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा

अंतिम छोर तक मिले योजनाओं का लाभ

भोपाल, 8 जून. पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए, जिससे समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुगमता से पहुंचे सके.

मंत्री पटेल ने विकास भवन में विभागीय योजनाओं के कार्यों,



वित्तीय प्रावधान और व्यय की योजनावार समीक्षा की. मंत्री पटेल ने निर्देशित किया कि जिन योजनाओं में इस तिमाही में व्यय कम हुआ है, वहां कार्यों की गति को तत्काल बढ़ाया जाए और भारत सरकार से संबंधित मुद्दों पर निरंतर फॉलो-अप कर शीघ्र

कार्यवाही की जाए. उन्होंने 'जन मन' योजना की किश्त का समय पर भुगतान करने, सोशल ऑडिट के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का निर्माण करने तथा 'बीबी रामजी योजना' के लिए वास्तविकता के आधार पर बजट तैयार करने के निर्देश दिए. पटेल ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, रसोइयों को मानदेय, मुख्यमंत्री आवास मिशन, रेडी टू टेक होम राशन की समीक्षा की.

सलामतपुर में जिला स्तरीय युवा संगम मेला आज

सलामतपुर. जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार 9 जून को सांची विकासखण्ड अंतर्गत एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलामतपुर में जिला स्तरीय युवा संगम मेले का आयोजन किया जा रहा है. जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वधान में आयोजित यह युवा संगम मेला मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक आयोजित होगा.

19 तक भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5 जून से शुरू हो चुकी है. अभ्यर्थी 19 जून तक ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं. वहीं विद्यार्थी आवेदन पत्र में सुधार आवेदन की तिथि से अंतिम तिथि 24 जून कर सकेंगे. बता दें मंडल द्वारा परीक्षा का आयोजन 10 जुलाई प्रारंभ किया जाएगा. यह परीक्षा दो अलग-अलग पालियों में कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन पद्धति से संपन्न होगी.

महाविद्यालयों की कुल 1100 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. इसमें स्ववित्तीय सरकारी एनिमल हब्सैंड्री डिप्लोमा महाविद्यालयों जबलपुर, महु, रीवा, मुँरेना और भोपाल में कुल 500 सीटें शामिल हैं. इसके अलावा निजी एनिमल

हब्सैंड्री डिप्लोमा महाविद्यालयों ग्वालियर, इंदौर, बड़वानी, हरदा और बालाघाट में कुल 500 सीटें निर्धारित हैं. वहीं निजी डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय विदिशा में कुल 100 सीटें उपलब्ध हैं.

हार्वस्टर की चपेट में आने से महिला की मौत

सिलवानी, 8 जून. जैथारी क्षेत्र में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. शाहजहां 56 वर्ष पति मो. सफ़ीक़ निवासी ग्राम रमपुरा सुल्तानपुर मोड़ ग्राम लोवंशी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे. आयुक्त बर्णवाल ने कहा कि अधिकारी किसानों से आग्रह करें कि उद्यानिकी में अपार संभावनाएँ हैं, किसानों के बीच जाकर उद्यानिकी को रकबा अधिक बढ़ाने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करें. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंत्रानुसार कम मूल्य की फसलों के बजाय अधिक मूल्य वाली फसलों का उत्पादन अधिक करें.

पोषण संजीवनी अभियान ने पेश की मिसाल

नवभारत न्यूज भोपाल, 8 जून. प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए निरंतर अभिनव और नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में विदिशा जिले से सफलता की एक ऐसी गौरवशाली गाथा सामने आई है, जिसने पूरे राज्य के सामने प्रशासनिक सुझबुझ और जनभागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 'स्वस्थ मध्यप्रदेश' के संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतारते हुए विदिशा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए 'पोषण संजीवनी अभियान' ने गंभीर कुपोषण के खिलाफ एक निर्णायक और प्रभावी जंग छेड़ दी है.

जून 2025 में हुए एक व्यापक सर्वे के दौरान जिले में 1,307 गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान होने पर समस्या की गंभीरता और स्पष्ट हो गई. इसी चुनौती को एक बड़े अवसर में बदलते हुए विदिशा जिला कलेक्टर अंशुल गुप्ता के नेतृत्व में 'पोषण संजीवनी अभियान' की परिकल्पना की गई, जिसका मूल ध्येय बच्चों का तात्कालिक उपचार नहीं बल्कि उनका दीर्घकालिक सुपोषण सुनिश्चित करना था. समाज के सामूहिक प्रयासों से देखते ही देखते 39.21 लाख की सम्मानजनक राशि स्वेच्छा से एकत्र हो गई, जिसके माध्यम से अब तक सभी 1,307 बच्चों तक सुपोषण किट पहुंचाई जा चुकी

अभियान के तहत प्रत्येक विन्धित गंभीर कुपोषित बच्चे को तीन महीने तक अतिरिक्त पोषण देने के लिए 3000 मूल्य की विशेष 'सुपोषण किट' प्रदान की जा रही है. इस पूरे अभियान की सफलता के पीछे जनभागीदारी एक प्रमुख कारण बना. इस पुनीत कार्य में समाज के विभिन्न वर्गों, स्थानीय व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने अभूतपूर्व संवेदनशीलता का परिचय दिया.

यह जनसहयोग इस बात का सशक्त प्रतीक है कि समाज अपने नौनिहालों के स्वास्थ्य के प्रति कितना सजग और उत्तरदायी है.

प्रदेश के संविदाकर्मियों का वेतन 4.46 फीसदी बढ़ेगा

3800 रुपए तक प्रतिमाह का होगा फायदा

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 8 जून. प्रदेश के एक लाख से अधिक संविदाकर्मियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. संविदाकर्मियों का वेतन अब प्रतिमाह 4.46 फीसदी तक बढ़ जाएगा.

वित्त विभाग ने सोमवार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4.46 फीसदी बढ़ोतरी संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं. इससे संविदाकर्मियों को प्रतिमाह 3800 रुपए तक फायदा होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने 22

जुलाई 2023 को इस संबंध में नीति जारी की थी, जिसमें इस संबंध में प्रावधान किया गया था. संविदा नीति में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही संविदा कर्मचारियों के वेतन आदि में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी की जाती है. नया सीपीआई एक अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा. पिछले 2.94 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी. लिहाजा इस बार अधिक बढ़ोतरी का फायदा संविदाकर्मियों को मिलेगा. सबसे अधिक ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रों को प्रतिमाह 3800 रुपए तक का फायदा होगा, वहीं संविदा में सेवा दे रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1200 रुपए तक का लाभ मिलेगा.



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

EOI No.-HYU/Registrar/2026/967	Durg, Date: 05-06-2026
Hemchand Yadav University, Durg (C.G.) invites Expression of interest (EOI) from eligible and experienced organizations/agencies/companies for establishing an Entrepreneurship, Incubation & Start-up Ecosystem at the University campus in alignment with NEP 2020, Atal Innovation Mission, Startup India and MSME schemes.	
Scope: Setting up & operating Incubation Centre Mentorship & Training Programs Start-up Support & Funding Linkage IPR/Patent Assistance Industry-Academia Collaboration MSME Scheme Implementation Digital Platform & Networking Monitoring & Impact Assessment.	
Eligibility: Registered entity in India Min 3 years experience in incubation/entrepreneurship Min 10 startups incubated Prior experience with academic institutions (preferred) DPHT/NITI Aayog/MSME recognized (preferred) Financially sound (3-year audited accounts required) Not blacklisted.	
Focus Areas: AgriTech Health Tech AYUSH EdTech Clean Tech Mining Tech AI/ML & IT Tribal Art & Craft Food Processing Rural & Social Entrepreneurship	
Last Date: 22 June 2026, 5:00 PM Detailed EOI document available at www.durguniversity.ac.in	
Submit to: Vice-Chancellor, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg-491001 (C.G.) Email: vc@hyudurg.ac.in	
-Sd- Registrar	
48071/2	

कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरोली, जिला सिंगरोली (म.प्र.)

क्रमांक/...../ई-टेंडरिंग/2025-26 सिंगरोली, दिनांक 08/06/2026
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्रमांक	टेंडर जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य		निविदा प्रपत्र		निविदा की अंतिम तिथि
				समयावधि	लागत	मूल्य	EMD	
1	2026_UAD_514067_1	08-06-2026	Appointment of Independent Engineer for Solid Waste Management (ISWM) Project comprising of Door to Door Collection, Transportation, Processing and construction, operation and maintenance of Regional Landfill Facility for Singrauli	60 Months	0	10,000	100,000	08/08/2026
2	2026_UAD_514035_1	08-06-2026	Demolition of Over Tank at Ward No.42 Near MPEB Office	15 Days	700,000	2,000	14,000	23-06-2026
3	2026_UAD_513774_1	08-06-2026	Supply of Submersible Motor Pump Set in Central Store	2 Months	8,39,748	2,000	16,795	22-06-2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संसोधन का प्रकाशन ऑनलाइन <http://mptenders.gov.in> की वेबसाइट पर ही किया जावेगा. पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा.

कार्यपालन यंत्रि नगर पालिक निगम सिंगरोली